

संपादकीय

जब आपका चेहरा ही आपका दुश्मन बन जाए

कल्पना

कोजिए, किसी ने आपकी आवाज चुरा ली है, आपके चेहरे पर आपके ही जैसा दूसरा चेहरा लगा दिया है और आपके नाम से बीमा का पैसा निकाल लिया है। यह कल्पना नहीं है, बल्कि डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर का सबसे बड़ा सच है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा में हुआ चौबीस घंटे का मंथन इसी खतरे को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जहाँ तीन सौ से अधिक छात्रों की एक सौ छह टोलियों ने एआई से होने वाली साइबर ठगी को मात देने की चुनौती स्वीकार की। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ठगी का तरीका बदल चुका है। अब चाकू और बंदूक नहीं, बल्कि कैमरा और कोड से लूट होती है।

बीमा क्षेत्र में डीपफेक तकनीक से फर्जी दुर्घटनाओं के वीडियो बनाए जा रहे हैं। सिंथेटिक आइडेंटिटी यानी नकली डिजिटल पहचान बनाकर पॉलिसी ली जा रही है और फिर फर्जी क्लेम के जरिए करोड़ों रुपये निकाले जा रहे हैं। आम आदमी को लगता है कि इससे केवल कंपनी को नुकसान हो रहा है, लेकिन असली नुकसान हम सबका है। कंपनियां इस तरह के नुकसान की भरपाई प्रीमियम बढ़ाकर करती हैं और अंततः उसका बोझ आम उपभोक्ता की जेब पर ही आता है। यानी डिजिटल दुनिया की यह लूट सीधे हमारी जेब पर वार कर रही है। इसी चुनौती का जवाब तलाशने के लिए बीआईटी मेसरा और टेक कंपनी एड्सोनिक ने मिलकर पहल की है। दो हजार बाईस से शुरू हुई उनकी साझेदारी दो हजार चौबीस में पाँच करोड़ रुपये के निवेश से बने डिजिटल इनोवेशन लैब के रूप में सामने आई। इस लैब में छात्रों को ऐसे हाई एआई टूल बनाने की चुनौती दी गई, जो फर्जी वीडियो और फर्जी पहचान को सेकंडों में पकड़ सकें। दूसरी चुनौती ऐसे रिटैवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम की थी, जो एआई को झूठ नहीं, सच बोलना सिखाए और एजेंटिक स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इंटेलिजेंस तैयार करे, यानी एआई केवल तेज नहीं, ईमानदार भी हो। दो अक्टूबर से शुरू हुआ यह अभियान चार अक्टूबर को इक्कीस टोलियों के अंतिम प्रदर्शन के साथ पूरा हुआ।

इस हैकार्थन की सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि यह किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन की चुनौती से जोड़ता है। एड्सोनिक के संस्थापक मयंक ने कहा कि छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उद्योग की असली चुनौतियों से परिचित करना जरूरी है। लैब के प्रमुख डॉ. मनोष कुमार पांडे ने भी सही कहा कि समस्या ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि ज्ञान को असली जीवन में लागू करने की हिम्मत की है। यही हिम्मत साइबर ठगी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। साइबर ठग अब वीडियो कॉल पर आपके बेटे की आवाज में बात कर सकते हैं, आपके बांस का चेहरा बनाकर पैसा ट्रांसफर करने को कह सकते हैं और बीमा अधिकारी बनकर भेजे गए एक लिंक के जरिए आपका डेटा चुरा सकते हैं। इसलिए तकनीक से बनी ठगी का जवाब तकनीक से देना होगा, लेकिन उससे भी जरूरी है जागरूकता। हर अनजान वीडियो कॉल को शक की नजर से देखना होगा, हर लिंक पर क्लिक करने से पहले रुकना होगा और अपनी डिजिटल पहचान को हर जगह साझा करने से बचना होगा। पहले देश की रक्षा सीमा पर होती थी, अब उसकी एक महत्वपूर्ण सीमा सच पर है। बीआईटी मेसरा के युवा कोडर नग साइबर प्रहरी की भूमिका में सामने आए हैं। जरूरत है कि देश के हर कॉलेज में ऐसी इनोवेशन लैब बनें, जहाँ छात्र केवल डिग्री के लिए नहीं, देश की डिजिटल सुरक्षा को कूट लोड़ें। सरकार और कंपनियां अपने स्तर पर सुरक्षा तंत्र तैयार कर सकती हैं, लेकिन अंततः एक गलत क्लिक पूरी व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। इसलिए एआई के इस दौर में सबसे जरूरी सुरक्षा उपकरण हमारी अपनी सतर्कता है। जब हर नागरिक साइबर प्रहरी बनेगा, तभी हम एआई वाली ठगी को हरा पायेंगे।

आजकल

दावे फाइलों में, हकीकत चौराहों पर

एक तरफ सरकार और जिला प्रशासन बड़े मंचों से दावा करता है कि शहरों को भिखारी मुक्त कर दिया गया है। पोस्टर लगाए जाते हैं कि भिक्षावृत्ति समाप्त हो गई है, पुनर्वास हो गया है और शहर अब स्वच्छ एवं व्यवस्थित है। लेकिन राजधानी में ही हर चौराहे पर हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। सुबह से शाम तक बुजुर्ग, युवा और छोटे-छोटे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। वे गाड़ियों के शोशे खटखटाते हैं, हाथ फैलाते हैं और कई बार तो गाड़ियों के सामने तके आ जाते हैं। यह उसी शहर का दृश्य है, जहां से भिखारी मुक्त करने का दावा करने वाले अधिकारी रोज गुजरते हैं।

पहले चौराहों पर जाम का कारण अतिक्रमण या सिमनल की खराबी माना जाता था, लेकिन अब भिखारियों की भीड़ भी यातायात के लिए परेशानी बन रही है। लाल बत्ती होते ही दस से पंद्रह लोग गाड़ियों के बीच पहुंच जाते हैं। कोई गोद में बच्चा लिए है तो कोई लाठी के सहारे खड़ा है। इससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है। कई बार भीख न देने पर अभद्रता की शिकायतें भी सामने आती हैं। इस पूरी स्थिति में यातायात पुलिस की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। चौराहों से कुछ ही दूरी पर हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच होती है, चालान काटे जाते हैं, लेकिन सड़क के बीच यातायात बाधित करते लोग नजर नहीं आते। क्या हेलमेट न पहनना ही अपराध है और यातायात बाधित करना नहीं? पुलिस की जिम्मेदारी केवल चालान काटना नहीं, यातायात को सुगम बनाना भी है। भिखारी मुक्त अभियान का उद्देश्य केवल कुछ लोगों को पकड़कर आश्रय गृह में रखना और फोटो खिंचवाना नहीं हो सकता। स्थायी पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की व्यवस्था के बिना वे फिर चौराहों पर लौटेंगे। गरीबी, बेरोजगारी और मानव तस्करी जैसे कारणों पर काम किए बिना यह समस्या खतरा नहीं होगी। चौराहों पर भीख मांगते बच्चे स्कूल में, बुजुर्ग आश्रय में और युवा रोजगार में होने चाहिए। शहर को भिखारी मुक्त करने का दावा करना आसान है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए ईमानदार और निरंतर प्रयास जरूरी है। जब तक फाइलों के दावे जमीन की हकीकत से नहीं मिलेंगे, तब तक राजधानी की चमक अधूरी ही रहेगी।

भारत अंगूठा

भारत अंगूठा था। अंगूठा लगा और राशन मिला, अंगूठा लगा और पेंशन आई। लेकिन अंगूठा कई बार धोखा दे जाता था। मसदूर के हाथ में मिट्टी, बुजुर्ग की उंगलियों में झुर्रियां और मशीन में नेटवर्क की कमी के कारण हकदार को भी भीख मांगनी पड़ती थी। अब सरकार ने इस पुरानी परेशानी का नया हल निकाला है। चेहरा ही पहचान है। नया सिस्टम कहता है कि अब आधार का सत्यापन फेस ऑथेंटिकेशन से होगा। यानी चेहरा दिखाओ और काम कराओ। यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि भरोसे का भी है।

ईपीडीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव फेस रिकॉग्निशन है। पहले फिंगरप्रिंट या आइरिस से राशन मिलता था, अब चेहरे को भी जोड़ा गया है। इससे फर्जी राशन कार्ड और डुप्लीकेट लाभार्थियों पर लगाम लगेगी। देश में मुक्त और रियायती राशन वितरण में होने वाली धोधली पर अंकुश लगेगा। कई बार स्कैनिंग में तकनीकी दिक्कतों के कारण जरूरतमंदों को खाली हाथ लौटना पड़ता था। अब चेहरे के जरिए सटीक सत्यापन हो सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आधार को अब तेईस आधिकारिक भाषाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि गांव का आदमी भी अपनी भाषा में इसे समझ

नईदुनिया

प्रदेश के युवाओं के ‘मन की बात’ सुनेंगे मोहन

डॉ. शिशिर उपाध्याय

मध्य प्रदेश

राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में एक बड़ा मंच सज रहा है। नाम है सीएम यूथ कॉन्क्लेव 2026। सरकार का दावा है कि यहां 20 हजार युवाओं से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीधा संवाद करेंगे। यह संवाद केवल भाषण नहीं होगा, बल्कि कौशल, स्वरोजगार, उद्यमिता और नवाचार की जानकारी देने का प्रयास होगा। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान और बार-बार होने वाले युवाओं के आंदोलनों को देखते हुए अब सरकार भी युवाओं को जोड़ने के लिए सीधा संवाद करने जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग 6 अक्टूबर को बड़ा आयोजन करेगा। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं को साधने की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। क्यों जरूरी है युवाओं से सीधा संवाद—

आज का युवा केवल नौकरी मांगने वाला नहीं है, वह नौकरी बनाने वाला बनना चाहता है। लेकिन उसके मन में कई सवाल हैं। पढ़ाई के बाद रोजगार कहां मिलेगा? स्कूल कहां से सीखें? स्टार्टअप के लिए पैसा कहां से आएगा? सरकारी योजनाएं कागजों में हैं या जमीन पर भी हैं? इन सवालों का जवाब युवा अब मंचों पर नहीं, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री से चाहता है। सीएम यूथ कॉन्क्लेव इसी जरूरत की पूर्ा करने की कोशिश है, जहां विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और नवोदित उद्यमों की प्रदर्शनी लगेगी। सहभागिता से युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार की

बदलती आवश्यकताओं से जोड़ा जाएगा।

कौशल और रोजगार का नया संगम: इस कॉन्क्लेव में 17 शासकीय विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता रहेगी। कॉन्क्लेव में विभाग, संस्थान, विश्वविद्यालय और नवोदित उद्यमों के 80 से अधिक प्रदर्शनी कक्ष लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर के माध्यम से नवाचारों का प्रदर्शन होगा। साथ ही एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ईवी आदि क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोजगार की संभावनाओं से युवाओं को परिचित कराया जाएगा। यह केवल प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि भविष्य की झलक है, जहां युवा देख सकेगा कि आने वाला समय किस तकनीक का है और उसे किस क्षेत्र में अपने आप को तैयार करना है।

लाल परेड मैदान में क्या कुछ खास होगा: लाल परेड मैदान में कार्यशाला स्थल, प्रदर्शनी कक्षों सहित आयोजन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। मंत्री इंद्र सिंह परमार ने सभी व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण करने तथा युवाओं की सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। एसपीएस अनुपम राजन और आयुक्त प्रबल सिपाहा भी मौजूद हैं। जानकारी दी जाएगी कि पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल और मुंबई के कबीर कैफे की संगीतमय प्रस्तुतियां भी खास आकर्षण होंगी। उच्च शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और उद्यमिता की दिशा में यह आयोजन युवाओं के लिए एक उत्सव जैसा होगा, जहां ज्ञान के साथ मनोरंजन भी होगा।

विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता

सपनों की डिग्री और हकीकत की दीवार जब काबिलियत को कागज ने रोक दिया

मध्य प्रदेश

में हजारों युवा दिन-रात एक कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं। वे नेट निकालते हैं, सेंट निकालते हैं, पीपचडी करते हैं, लिखित परीक्षा में पसीना बहाते हैं और जब मेरिट में नाम आता है तो लगता है कि मंजिल मिल गई। लेकिन दस्तावेज जांच की टैबल पर वही सपना टूट जाता है। कहा जाता है कि आपकी डिग्री इस विषय से मेल नहीं खाती, आप अयोग्य हैं। हाल ही में चार प्रतिभागियों के साथ यही हुआ और मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा। तीन प्रतिभागियों को राहत मिली और एक को नहीं मिली। यह कहानी सिर्फ चार लोगों की नहीं है, यह उस पूरी पीढ़ी की कहानी है जो नई पढ़ाई पढ़कर पुरानी भर्ती व्यवस्था में फंस रही है।

उच्च शिक्षा विभाग ने प्राणीशास्त्र के लिए ग्यारह सह विषयों की सूची तय की थी। उस सूची में बायोटेक्नोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान जैसे विषय भी शामिल थे, लेकिन भर्ती एजेंसी ने बायोटेक्नोलॉजी में तकनीकी डिग्री को प्राणीशास्त्र के लिए मान्य नहीं माना। एक प्रतिभागी के पास बायोटेक्नोलॉजी में उच्च तकनीकी डिग्री थी। साथ में जीवन विज्ञान में राष्ट्रीय पात्रता और जैव विज्ञान में शोध उपाधि भी थी। फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया। न्यायालय ने विभागीय आदेश को ही आधार बनाया और कहा कि जब विभाग ने खुद बायोटेक्नोलॉजी को सह विषय माना है तो उसे अमान्य कैसे किया जा सकता है। उन्हें राहत दे दी गई। यानी सूची में हो तो ही मान्य, वरना नहीं।

इसी तर्क पर उस प्रतिभागी को भी राहत मिली, जिनके पास प्राणीशास्त्र में स्नातकोत्तर और पर्यावरण विज्ञान में राष्ट्रीय पात्रता थी। पर्यावरण विज्ञान सूची में था, इसलिए मान्य हो गया। संगीत विषय के प्रतिभागी को भी संगीत में ही स्नातकोत्तर और राज्य व राष्ट्रीय पात्रता होने के कारण राहत मिल गई। लेकिन एक प्रतिभागी को राहत नहीं मिली, क्योंकि उनका विषय एनिमल बायोटेक्नोलॉजी था, जो ग्यारह सह विषयों की सूची में शामिल नहीं था। उन्होंने समकक्षता प्रमाण पत्र भी लगाया था, लेकिन न्यायालय ने साफ कहा कि समकक्षता तय करना विशेषज्ञों का काम है। सिर्फ प्रमाण पत्र के आधार पर सूची से बाहर के विषय को जोड़ा नहीं जा सकता।

आज की शिक्षा बदल गई है। अब कोई



विषय अकेला नहीं पढ़ाया जाता। जीव विज्ञान तकनीक से जुड़ गया है, पर्यावरण विज्ञान जीव विज्ञान से जुड़ गया है और संगीत भी अब विज्ञान और तकनीक से जुड़ रहा है। नई शिक्षा नीति कहती है कि अंतरविषयक पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी भी पुरानी लोक पर चल रही है। वह अभी भी कहती है कि प्राणीशास्त्र के लिए सिर्फ प्राणीशास्त्र की डिग्री चाहिए। यह विरोधाभास युवाओं को भ्रम में डाल रहा है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे नए विषय पढ़ें या पुराने विषयों तक ही सीमित रहें।

जब एक युवा सात साल तक शोध करता है, लाखों रुपये खर्च करता है, परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाता है और दस्तावेज जांच में अयोग्य घोषित हो जाता है तो उसका हौसला टूट जाता है। कई युवा उस सीमा पर कर जाते हैं, कई मानसिक तनाव से गुजरते हैं। यह सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, यह पूरे समाज का नुकसान है, क्योंकि योग्य शिक्षक बाहर हो जाते हैं और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए वही पुरानी सोच वाली व्यवस्था बनी रहती है। इसका सीधा असर छात्रों की गुणवत्ता पर पड़ता है और प्रदेश की उच्च शिक्षा कमजोर होती है। छात्रों को अब जागरूक होना होगा। सिर्फ विज्ञापन पढ़कर आवेदन करना काफी नहीं है। विभागीय आदेश, सह विषय सूची और न्यायालय के फैसलों को भी पढ़ना होगा। यदि आपके पास



का मंत्र: सरकार का लक्ष्य है कि युवा केवल सरकारी नौकरी के पीछे न भागे, वह स्वरोजगार की ओर बढ़े। कॉन्क्लेव में इसी मंत्र को दोहराया जाएगा कि अपना काम शुरू करो, सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री का सीधा संवाद इसी बात पर केंद्रित होगा कि मध्य प्रदेश के युवा कैसे आत्मनिर्भर बनें, कैसे वे स्टार्टअप शुरू करें और कैसे कौशल सीखकर रोजगार पाएं। यह विचार नया नहीं है, लेकिन इसे 20 हजार युवाओं के बीच सीधे रखना एक बड़ा प्रयोग है। अगर युवा इस संवाद से प्रेरित होकर अपने पैरों पर खड़ा होता है तो यह कॉन्क्लेव सफल माना जाएगा।

राजनीति से परे युवाओं का सवाल:

एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी युवाओं के मुहों को लेकर सड़कों पर हैं, छात्रों की आवाज बन रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा सरकार युवाओं को अपने पाले में

समग्र विकास से सिद्धि

(मोदी जी के शासन के 25 वर्षों पर आलेख)

अखिलेश जैन के 25 वर्षों के शासनकाल में

भारत की यात्रा वास्तव में समग्र विकास से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों की यात्रा है।

अपरिवर्तनशील वास्तविकता है कि सूर्य पूर्व में ही उगता है। उसी तरह शाश्वत सत्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत निराशा, भाई-भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कालेधन, जमाखोरी, आयात पर निर्भरता, तुष्टीकरण, संस्कृति के अपमान और गुलामी के प्रतीकों जैसी तमाम बेड़ियों को तोड़कर सुंदर, सुखद भविष्य के निर्माण हेतु रात-दिन एक करके, बिना रुके, बिना थके, बिना दाएं-बाएं देखे कठिन से कठिन अगिन परीक्षा जैसी चुनौतियों को पार करके भविष्य निर्माण में जुटा हुआ है।

आज भारत का लक्ष्य, ध्येय, सपना, नारा, वचन तथा एक ही दशरथ नंदन प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही चरणों में प्रार्थना है, ‘विकसित भारत @2047’।

‘विकसित भारत @2047’ लक्ष्य की गहराई को जानने वाले ही लक्ष्य की गंभीरता को समझ सकते हैं। नारा आसान है, लक्ष्य गंभीर है। ‘विकसित भारत @2047’ की लक्ष्य सिद्धि के लिए उससे भी बड़ा तप करना पड़ेगा, जितना तप महाराज भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए किया था। महाराज भगीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने का वरदान दिया था। महाराज भगीरथ का लक्ष्य ही निजता का खड़ा है। जीडीपी, जीएसटी व आयकर शिखर पर हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। अगर सफलता की गति बरकरार रहती है तो 5 ट्रिलियन डॉलर की लक्ष्य है। इस सिद्धि को पाने के पहले तमाम सिद्धियां पार करनी पड़ेंगी, तमाम बाधाओं को पार पाना पड़ेगा, जो मुख्य सिद्धि के मार्ग में बाधा हैं।

(बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ

गांव का युवा भी समझ सके कि वह अपने खेत के उत्पाद से कैसे स्टार्टअप बना सकता है और शहर का युवा कैसे एआई में अपना भविष्य बना सकता है। यह तकनीक और परंपरा का मेल ही मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

संवाद से समाधान तक की यात्रा: 20 हजार युवाओं से सीधा संवाद करना आसान नहीं है, लेकिन यही संवाद लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब मुख्यमंत्री युवाओं के बीच बैठकर उनकी बात सुनेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे तो युवाओं में भरोसा पैदा होगा। यह भरोसा ही सरकार और समाज के बीच पुल का काम करता है। कॉन्क्लेव में केवल योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि युवाओं से सुझाव भी लिए जाएंगे कि वे क्या चाहते हैं और सरकार को क्या करना चाहिए। यह दो तरफा संवाद ही इस आयोजन को बाकी आयोजनों से अलग बनाता है।

भविष्य की तैयारी: आज का युव कल का भविष्य है। अगर उसे सही दिशा मिल गई तो प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल है। सीएम यूथ कॉन्क्लेव 2026 इसी भविष्य की तैयारी है। यहां युवाओं को बताया जाएगा कि रोजगार केवल सरकारी दफ्तर में नहीं है। रोजगार खेत में भी है, लैब में भी है और अपने छोटे से स्टार्टअप में भी है। जरूरत है तो बस सही कौशल और सही जानकारी की। यह कॉन्क्लेव वही जानकारी देने का बड़ अवसर है। अगर इसका सही उपयोग हुआ तो यह मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक नया सबरा लेकर आएगा और लाल परेड मैदान से निकली यह आवाज पूरे प्रदेश में गूँजेगी।

समग्र विकास से सिद्धि

(मोदी जी के शासन के 25 वर्षों पर आलेख)

बाधाओं को दूर करने की गति को भी गति देना पड़ेगा।

मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ चुका है। 12वीं अर्थव्यवस्था से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। महिलाएं नीति निर्णयों में भागीदार बन रही हैं। अर्थव्यवस्था की मजबूती व स्थायित्व में महिलाओं का योगदान लाने में भारत सफल हो रहा है। 2014 से भ्रष्टाचार की खबरों को मसाला न मिलने के कारण जनता में उत्साह का संचार करने में सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसके सकारात्मक परिणाम बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, परिंदा भी पर नहीं मार पाता, क्योंकि सरकार व सेना की कार्यवाहियों का लेखा-जोखा नेत्रहीन ही तुरंत पढ़ लेता है। सरकार का आतंकवाद विरोधी नियंत्र देश में स्थिरता, शांति व प्रगति लाने में सहायक हुआ है।

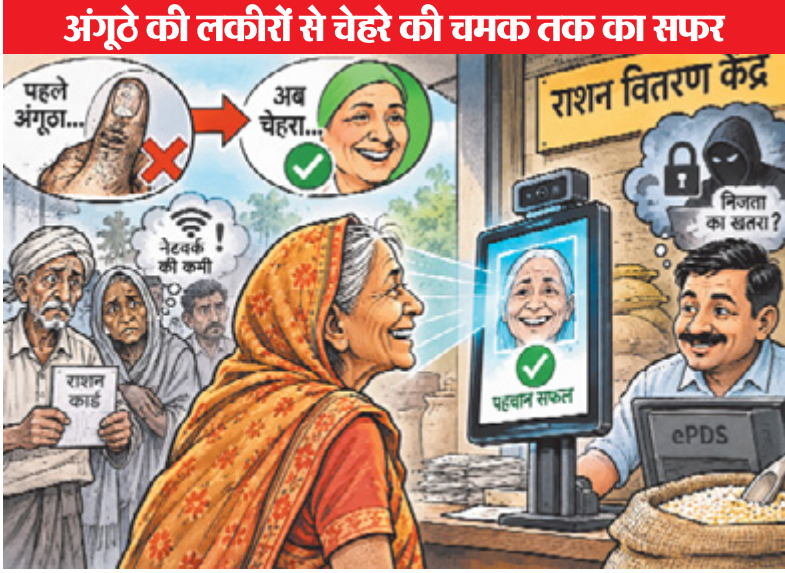
आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की खोज व विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सनातन संस्कृति की रक्षा व संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण व रोजगार की संभावनाएं, करों का सरलीकरण, हर व्यक्ति का बैंक में खाता, गरीब को चिकित्सा सुविधा, आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, शौचालय, दिल्ली से चली राशि बिना किसी कट के सीधे हितग्राहियों के खाते में बराबर व तुरंत हितप्रधान, 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने आर्थिक प्रगति में जो योगदान दिया है, उसी कारण विदेशी निवेश भारत के दरवाजे का लड़खे लगाकर खड़ा है। जीडीपी, जीएसटी व आयकर शिखर पर हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। अगर सफलता की गति बरकरार रहती है तो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था व ‘विकसित भारत @ 2047’ की सिद्धि पाने में भारत शीघ्र सफलता पाएगा।

(लेखक भाजपा मप्र के कोषाध्यक्ष हैं)

गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और डेटा लोक का डर कम होगा।

प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों में भीड़ लगती है। लोग सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं। अब टोकन मैनेजमेंट सिस्टम से काम होगा। विजिटर वेरिफिकेशन आसान होगा और काम की मॉनिटरिंग होगी। इससे समय बचेगा और दलाली खत्म होगी। पहले लोग पूछते थे कि नंबर क्या आएगा, अब सिस्टम खुद बताएगा।

तकनीक आकर्षक है, पर सवाल भी उतने ही बढ़ें हैं। चेहरा अंगुठे की तरह स्थिर नहीं है। उम्र के साथ बदलता है। दाढ़ी, मूँछ, चश्मा, घूंघट और बीमारी से चेहरा बदल जाता है। क्या सिस्टम हर बार पहचान पाएगा? गांव में जहां नेटवर्क नहीं, बिजली नहीं और कैमरे की क्वालिटी खराब है, वहां चेहरा पहचानना कितना आसान होगा? राशन दुकानदार को नया फोन मिलेगा या पुरानी मशीन से ही काम चलाना पड़ेगा? बुजुर्ग महिला को घूंघट में रहती है, उसका सत्यापन कैसे होगा? यदि इन सवालों का जवाब नहीं खोजा गया तो यह योजना शहरों के मौल तक सिमट जाएगी और गांव का गरीब फिर से तकनीक और भूख के बीच फंसा रहेगा।



लेकिन निजता भी बचेगी। चेहरे की फोटो को स्टोर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे एक टोकन में बदला जाएगा। टोकन सिस्टम का

मतलब है कि आपका चेहरा कहीं सेव नहीं होगा, बस एक कोड बनेगा, जो सत्यापन के बाद खत्म हो जाएगा। इससे किसी के चेहरे का